आर्थिक सर्वेक्षण, दिल्ली 2019–20 : मुख्य बातें

दिल्ली की अर्थव्यवस्था

1. अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2019–20 के दौरान दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर 856112 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जो 2018–19 की तुलना में 10.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

2. प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, में पिछले 5 वर्ष के दौरान 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और यह 2015–16 के 5,50,804 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019–20 में 8,56,112 करोड़ रुपये हो गया है। वास्तविक रूप से, 2019–20 के दौरान विकास दर 7.42 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो राष्ट्रीय विकास दर 5.0 प्रतिशत से अधिक है।

3. 2019–20 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर दिल्ली के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में तृतीयक क्षेत्र का योगदान 85.16 प्रतिशत रहा। इसके बाद माध्यमिक क्षेत्र (13.37 प्रतिशत) और प्राथमिक क्षेत्र (1.47 प्रतिशत) का स्थान है।

4. दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर 2019–20 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 134432 रूपये की तुलना में 389143 रुपये पर पहुंच जाने की संभावना है, इस तरह दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। दिल्ली भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है।

5. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने 2016–17 से 2020–21 की अवधि के लिए 5वें दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया है।

6. दिल्ली ने अपनी राजस्व अधिशेष की स्थिति निरंतर बनाए रखी है। 2018–19 के दौरान राजस्व अधिशेष 6261 करोड़ रुपये का रहा जबकि 2017–18 में यह 4913 करोड़ रुपये रहा था।

7. दिल्ली सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2018–19 (अनंतिम) में 1489.38 करोड़ रुपये था जो जीएसडीपी का 0.19 प्रतिशत था, जबकि इसकी तुलना में 2017–18 में 1569.16 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा था, जो जीएसडीपी का 0.23 प्रतिशत था।

8. वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आवंटित बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए 78.84 प्रतिशत बजट आवंटित किया गया।

9. वित्तीय वर्ष 2019–20 में शिक्षा क्षेत्र को प्रथम वरीयता जारी रही और कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आवंटित बजट का 28.96 प्रतिशत हिस्सा इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया। इसके बाद आवास और शहरी विकास (14.50 प्रतिशत), चिकित्सा और जन–स्वास्थ्य (13.93 प्रतिशत), परिवहन (13.73 प्रतिशत), सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (12.71 प्रतिशत), जलापूर्ति और स्वच्छता (8.78 प्रतिशत) का स्थान रहा।

पर्यावरण, वन और ग्रामीण विकास

10. दिल्ली में कुल वन और वृक्षाच्छादित क्षेत्र 2015 में 299.77 वर्ग किलोमीटर था, जो 2019 में बढ़कर 324.44 वर्ग किलोमीटर हो गया है। दिल्ली का हरित क्षेत्र 2015 में करीब 20.22 प्रतिशत था, जो 2019 में बढ़ कर 21.88 प्रतिशत हो गया है।

11. दक्षिण दिल्ली जिले में वन आच्छादित क्षेत्र सबसे ज्यादा 84.63 वर्ग किलोमीटर, और पूर्वी दिल्ली जिले में वन आच्छादित क्षेत्र सबसे कम 3.75 वर्ग किलोमीटर है।

12. वर्ष 2019 में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें 19 हरित एजेंसियों, पर्यावरण क्लबों और निवासी कल्याण संगठनों को शामिल करते हुए 21.15 लाख पौधे लगाए गए। इसके अतिरिक्त 4.57 पौधे रोपने के लिए जनता में भी बांटे गये।

13. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) 26 ऑनलाइन सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता नियंत्रन केन्द्रों के माध्यम से 26 स्थानों पर वायु की गुणवता पर निगरानी रख रही है।

14. दिल्ली की 2010–11 की कृषि गणना के आंकड़ों की 2015–16 की कृषि गणना के आंकड़ों से तुलना करें तो यहां खेती में इस्तेमाल की जा रही कृषि जोतों की संख्या में 1.68 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जबकि 2015–16 की कृषि गणना में 2010–11 की कृषि गणना की तुलना में दिल्ली में खेती के लिए प्रयुक्त क्षेत्र में 2.21 प्रतिशत की गिरावट आई है।

15. दिल्ली में पशु चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 49 सरकारी पशु चिकित्सालय, 26 पशु चिकित्सा औषधालय, 1 प्रयोगशाला/अनुसंधान केंद्र और 1 पशुचिकित्सा पोलिक्लिनिक है। सरकारी पशु चिकित्सा अस्पतालों/औषधालयों में उपचारित पशुओं की संख्या जो 2014–15 में 3.68 लाख थी, वह 2018–19 में बढ़कर 4.61 लाख पर पहुंच गई।

विद्युत और उद्योग

16. दिल्ली में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2018–19 में 59.94 लाख थी। पिछले 10 वर्षों में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में 74.81 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

17. दिल्ली में कुल बिजली खरीद पिछले दस वर्षों के दौरान 37.97 प्रतिशत बढ़ी है।

18. व्यस्तता के समय विद्युत की मांग 2014–15 में 5925 मेगावाट थी जो 2018–19 में बढ़ कर 7016 मेगावाट हो गई।

19. दिल्ली में कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए टी एंड सी) घाटा 2018–19 में घट कर 8.32 प्रतिशत रह गया, जो सुधार पूर्व अवधि में 52 प्रतिशत था।

20. दिल्ली में ग्रिड से जुड़ी सभी सौर बिजली परियोजनाओं ने जनवरी 2020 तक 162 मेगावाट का योगदान किया।

21. दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता 31.01.2020 को 214 मेगावाट (सोलर 162 मेगावाट + डब्ल्यूटीई 52 मेगावाट) दर्ज हुई।

22. कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्र दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे हैं। तेहखंड (25 मेगावाट) संयंत्र स्थापना का काम प्रगति पर हैं, भलस्वा में 15 मेगावाट क्षमता के संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है और गाज़ीपुर में स्थापित संयंत्र की क्षमता में 8 मेगावाट का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है।

23. दिल्ली की अर्थव्यवस्था में माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान विनिर्माण उप–क्षेत्र का है। विनिर्माण क्षेत्र से आय 2011–12 में 18907 करोड़ रुपये थी, जो 2019–20 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार बढ़ कर 35889 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

24. दिल्ली में चालू फैक्ट्रियों की संख्या 2014 में 8968 थी, जो 2018 में बढ़ कर 9121 हो गईं। इसी तरह, इन फैक्ट्रियों में कार्यरत अनुमानित श्रमिक 2014 में 416927 से बढ़कर 2018 में 419578 हो गए।

परिवहन

25. दिल्ली में मोटरवाहनों की कुल संख्या 31 मार्च, 2019 को 113.92 लाख पर पहुंच गई, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 3.69 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई।

26. 2018–19 में मैट्रो रेल में रोजाना औसतन 25.97 लाख यात्रियों ने सफर किया।

27. दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले से तीसरे चरण तक की लाइनों की लंबाई 350.03 कि.मी. है जिसमें से 59.111 कि.मी रूट कि.मी लाइनें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। चौथे चरण के पूरा हो जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की लाइनों सहित दिल्ली मेट्रो की मुल लंबाई 453.96 कि.मी. हो जाएगी।

28. सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में कॉमन मोबिलिटी कार्ड सुविधा लागू की गई है।

29. पुराने वाहनों को बदलने और विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ''दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019'' अनुमोदित की गई जिसका प्रमुख लक्ष्य परिवहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाते हुए दिल्ली की वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाना है।

30. रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 29.10.2019 से महिलाओं के लिए डीटीसी/क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा शुरू की है। महिलाओं के लिए वातानुकूलित और सामान्य दोनों ही तरह की बसों में एकल यात्रा आधारित 10 रुपये का 'पिंक' रंग वाला टिकट के आकार का पास दिया जाता है।

31. इस समय 58 बस डिपो काम कर रहे हैं और 12 का काम चल रहा है! इसके अलावा 16 बस टर्मिनल भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा द्वारका के सेक्टर 4 और सेक्टर 12, विकासपुरी और नरेला में भी टर्मिनलों के निर्माण का काम चल रहा है।

32. 2019–20 में फरवरी 2020 तक क्लस्टर योजना के अंतर्गत 733 नयी बसें शामिल की जा चुकी हैं।

33. सरकार ने सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए डीटीसी द्वारा बस कर्मचारियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्यक्रम नियमित रूप से चलाया जा रहा है।

34. दिल्ली में कुल 2.80 लाख सीसीटीवी कैमरा (हर विधानसभा क्षेत्र में 4000) वांछित स्थानों पर लगाने के लिए इनकी आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने का कार्य जारी है। दिसंबर 2019 तक निर्धारित स्थानों पर करीब 1,27,000 सीसीटीवी कैमरा लगाये जा चुके थे।

35. महिला यात्रियों की हिफाजत और सुरक्षा के लिए 13.11.2019 तक डीटीसी बसों में 7431 और क्लस्टर बसों में 2809 मार्शल तैनात थे।

आवास और जलापूर्ति

36. मौजूदा जल शुल्क ''अधिक इस्तेमाल के लिए अधिक भुगतान' के सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान जल शुल्क नीति पानी की अत्यधिक खपत करने वाले या पानी बर्बाद करने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रतिरोधक के रूप में काम करती है। डीजेबी ने 2018–19 के दौरान 1819.60 करोड़ रुपये का संग्रह किया था।

37. दिल्ली के करीब 83.42 प्रतिशत परिवारों को पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति सुविधा उपलब्ध है।

38. दिल्ली जल बोर्ड ने नागरिकों को कुशल और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पानी का बिल देने, ऑनलाइन भुगतान और अप्रत्याशित रूप से भारी रकम वाले बिलों की समस्या के समाधान के लिए सेवा ऐप की शुरुआत की है।

39. 31 मार्च, 2019 को दिल्ली जल बोर्ड की कुल उपचार क्षमता 12 जल उपचार संयंत्रों के साथ 911 एमजीडी थी।

40. दिल्ली जल बोर्डे के पास वितरण के लिए कुल जल संसाधन 937 एमजीडी उपलब्ध हैं, जिनमें से यमुना नदी (380 एमजीडी), गंगा नदी (250 एमजीडी), भाखड़ा स्टोरेज (221 एमजीडी) और 86 एमजीडी ट्यूबवेल, भूमिगत जल जैसे अन्य स्रोतों से उपलब्ध हैं।

41. दिल्ली जल बोर्ड की मल जल उपचार क्षमता 31 मार्च, 2019 को 607.26 एमजीडी है।

42. दिल्ली में 675 झुग्गी झोपड़ी बस्तियां हैं, जिनमें करीब 3.06 लाख झुग्गीवासी रह रहे हैं और ये बस्तियां 799 हेक्टेयर भूमि पर फैली हैं।

43. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड को खुले में शौच से मुक्त++ प्रमाणपत्र दिया गया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम खुले में शौच से मुक्त प्रमाणीकृत किये जा चुके हैं। उत्तर दिल्ली नगर निगम को भी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है।

44. स्व–स्थाने मलिन बस्ती पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य अनधिकृत कालोनियों में रह रहे लोगों को 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराना है।

शिक्षा

45. दिल्ली सरकार के अंतर्गत 1229 सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल हैं, जो दिल्ली में संचालित कुल स्कूलों का 21.46 प्रतिशत हैं, जबकि सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों की दाखिलों में हिस्सेदारी 2018–19 के दौरान कुल दाखिलों का 37.27 प्रतिशत थी।

46. डीआईएसई रिपोर्ट–2017 के अनुसार, दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा में सकल दाखिला अनुपात 109.19 प्रतिशत था, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह अनुपात 95.12 प्रतिशत था।

47. दिल्ली सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में निवेश में महत्वपूर्ण इजाफा किया है और शिक्षा के लिए बजट राशि 2014–15 की 6555 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2019–20 में 15601 करोड़ रुपये हो गई।

48. भारतीय रिजर्व बैंक की राज्य बजट विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा लगातार शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कर रही है जो देश के सभी राज्यों द्वारा इस क्षेत्र में निवेश किये जाने वाले हिस्से के अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2019–20 के दौरान दिल्ली ने अपने कुल बजट अनुमान का 26 प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जो सभी राज्यों से अधिक है। 2019–20 के दौरान राष्ट्रीय औसत 14.8 प्रतिशत था।

49. दिल्ली में सरकार द्वारा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष शिक्षा व्यय 2014–15 में 36041 रुपये था, जो 2018–19 में बढ़ कर 63172 रुपये हो गया।

50. आउट आफ स्कूल बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए 761 विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। इन केंद्रों में 29234 बच्चों ने नामांकन कराया।

51. डिजिटल शिक्षा (सरकारी स्कूल/आरपीवीवी) को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभा फेलोशिप शैक्षणिक सत्र 2019–20 से शुरु की गई है। इसका उद्देश्य राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय (आरपीवीवी) और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (एसओई) के तहत 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाले और क्लास 11वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर टेबलेट प्रदान करना है। 10949 ऐसे विद्यार्थियों को कम्प्यूटर टेबलेट उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

52. दिल्ली सरकार के स्कूलों द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविरों में 2.28 लाख विद्यार्थियों ने भागीदारी की।

53. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान के सहयोग से दिल्ली में एक विश्वस्तरीय कौशल विकास केंद्र की स्थापना की है।

54. 11 तकनीकी और उच्च शिक्षण संस्थानों में विशेष रूप से ध्यान देने के उद्देश्य से इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं।

स्वास्थ्य

55. दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र ढांचे के अंतर्गत 1432 औषधालय, 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1172 नर्सिंग होम, 251 प्रसूति गृह, 222 पोलीक्लिनिक्स/स्पेशल क्लिनिक्स, 88 अस्पताल और 17 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।

56. दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या 2014 में 48096 थी, जो 2018 में बढ़ कर 57709 हो गई जिससे इस अवधि के दौरान आबादी–बिस्तर अनुपात (प्रति 1000 व्यक्तियों पर बिस्तर) 2.65 से बढ़कर 2. 94 हो गया।

57. शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों के संदर्भ में दिल्ली का स्तर क्रमशः 16, 14 और 21 है, जो अखिल भारतीय स्तर क्रमशः 33, 23 और 37 की तुलना में कम है। दिल्ली की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 1.5 है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है।

58. दिल्ली में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च 2014–15 में 1996 रुपये था जो 2018–19 में बढ़ कर 3044 रुपये हो गया।

59. दिल्ली में 6035 आशा वर्कर काम कर रही हैं। एक आशा का चयन 1500–2500 की आबादी (300 से 500 परिवार) पर किया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

60. 60–69 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2500 रुपये प्रति माह प्रदान की जा रही है। भिन्न दृष्टि से सक्षम व्यक्तियों और संकटग्रस्त महिलाओं को भी 2500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

61. करीब 4.65 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिसंबर, 2019 तक) में मासिक वृद्धावस्था पेंशन दी गई और 2018–19 के दौरान करीब 4.42 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मासिक वृद्धावस्था पेंशन दी गई थी।

62. करीब 2.54 लाख 'मुसीबत में फंसी महिलाओं यानी विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक दृष्टि से पृथक और निस्सहाय महिलाओं' को 2019–20 (दिसंबर, 2019 तक) के दौरान मासिक वित्तीय सहायता दी गई और 2018–19 में यह संख्या 2.38 लाख थी।

63. 2019–20 (दिसंबर, 2019 तक) के दौरान 'भिन्न दृष्टि से सक्षम व्यक्तियों को वित्तीय सहायता' कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 93475 दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता दी गई। 2018–19 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 87196 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

64. दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना आरंभ की है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने और समुचित रोजगार प्राप्त करने में सफल होने के वास्ते गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना है।

65. वर्ष 2019–20 (दिसंबर, 2019 तक) में राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 5645 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

66. दिल्ली में 95 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के अंतर्गत 10897 आंगनवाड़ी केंद्रों का नेटवर्क है, जिनके अंतर्गत बच्चों (0–6 वर्ष की आयु) और गर्भवती महिलाओं/दूध पिलाने वाली माताओं को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, पूर्व–विद्यालय गतिविधियों, आदि का लाभ पहुंचाया जाता है। 2018–19 में लाभार्थियों की संख्या 12.72 लाख थी। 2019–20 (दिसंबर, 2019 तक) के दौरान लाभार्थियों की संख्या 12.91 लाख है।